प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 से परम्परागत उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सिल्क एक्सपो–2024 का उद्घाटन किया

❑ रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया

❑ उ0प्र0, देश का पहला ऐसा राज्य, जिसने परम्परागत उत्पादों के लिए स्वयं की नीति बनाई

❑ 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना के अन्तर्गत उत्पादों को बाजार, डिजाइनिंग, पैकेजिंग के साथ जोड़ा गया

लखन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 से परम्परागत उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश, देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने परम्परागत उत्पादों के लिए स्वयं की नीति बनाई है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के एक विशिष्ट उत्पाद को चिन्हित करते हुए आगे बढ़ाया गया है। यही कारण है कि आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद का स्वयं का एक यूनीक उत्पाद है, जिसे 'एक जनपद, एक उत्पाद' की संज्ञा दी गई है। 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना के अन्तर्गत उत्पादों को बाजार, डिजाइनिंग, पैकेजिंग के साथ जोड़ा गया। परिणामस्वरूप रोजगार के सृजन के साथ-साथ परम्परागत उत्पादों का निर्यात होना भी प्रारम्भ हुआ है। प्रदेश में 75 जी0आई0 उत्पाद मौजूद हैं, जिन्हें देश में मान्यता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री सिल्क एक्सपो-2024 का उद्घाटन करने के पश्चात इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने रेशम उत्पादन, व्यवसाय तथा रेशम फैशन डिजाइनिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आठ विभिन्न श्रेणियों के 16 कृषकों, उद्यमियों एवं संस्थाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न पुरस्कार के अन्तर्गत प्रतीकात्मक चेक, प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन भी किया।

इसके पूर्व, मुख्यमंत्री ने सिल्क एक्सपो में विभिन्न रेशमी उत्पादों का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने किसानों को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे समाज में रोटी, कपड़ा और मकान की कहावत प्राचीन काल से प्रचलित है। एक सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। कपड़ा जीवन की आवश्यकता है। यह किसान की आमदनी को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम है। प्राचीन काल से ही रेशम उत्पादन की अलग-अलग पद्धतियां रही हैं। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में अनेक सम्भावनाएं हैं। विगत कुछ वर्षों में प्रदेश ने इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है। यह प्रगति पहले की तुलना में संतोषजनक है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी और प्रयास की आवश्यकता है। सप्त दिवसीय सिल्क एक्सपो इसका माध्यम बनेगा। प्रदेश के किसान तथा उद्यमी रेशम वस्त्रोद्योग के क्षेत्र से प्राचीन काल से जुड़े रहे हैं। लेकिन समय के अनुरूप उन्हें उचित प्रोत्साहन, डिजाइनिंग तथा पैकेजिंग के साथ जुड़ने में पिछली सरकारों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। यह स्थिति परम्परागत उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिली।

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उ0प्र0 ने चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक लम्बी यात्रा बढ़ायी : मुख्यमंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0) में 1,147 करोड़ रूपये लागत की 04 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 03 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि दीपावली पर्व के उपहार स्वरूप देश व उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एस0जी0पी0जी0आई0 को एक साथ इतनी बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं। इनमें एडवांस डायबिटिक सेन्टर, टेली-आई0सी0यू0 परियोजना, सलोनी हार्ट सेन्टर-प्रथम चरण, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के 200 छात्रों हेतु हॉस्टल का लोकार्पण तथा एडवांस पीडियाट्रिक सेन्टर, सलोनी हार्ट सेन्टर-द्वितीय चरण व रैनबसेरा का शिलान्यास शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजनाएं सरकार, सामाजिक व धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से आगे बढ़ायी गयी हैं। इनसे एस0जी0पी0जी0आई0 की क्षमता में वृद्धि होगी तथा संस्थान अपनी शानदार यात्रा को इसी प्रकार आगे बढ़ा सकेगा। देश व प्रदेश के लोगों को इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। यह स्वास्थ्य परियोजनाएं समय से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक लम्बी यात्रा बढ़ायी है। विगत साढ़े सात वर्षों में राज्य के 64 जनपदों को मेडिकल कॉलेज हैं। जबकि

❑ मुख्यमंत्री ने एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में 1,147 करोड़ रू0 लागत की 04 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 03 परियोजनाओं का शिलान्यास किया

वर्ष 2017 से पूर्व केवल 18 जनपदों में मेडिकल कॉलेज थे। प्रदेश सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। राज्य में एम0बी0बी0एस0 व पी0जी0 की सीटें पहले की तुलना में दोगुने से अधिक हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान व्यक्ति के कार्यों के अनुसार स्थान व व्यक्ति दोनों को बनाता है। यदि हमारे कार्यों से संस्थान यशस्वी बनता है, तो हमारा कार्य भी यशस्वी होता है और हम यश के भागीदार बनते हैं। यदि हमारे कार्यों से संस्थान का यश गिरता है तो हम अपयश के भागीदार बनते हैं। एस0जी0पी0जी0आई0 की पूरी टीम यश की भागीदार है।

प्रदेश में बाल रोग से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए अब एस0जी0पी0जी0आई0 में 575 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेन्टर स्थापित होने जा रहा है।

सहकारिता
संरक्षक
बी०एन०सिंह (आई.ए.एस.)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0
श्रीकान्त गोस्वामी
प्रबन्ध निदेशक/प्रधान सम्पादक
सवीन्द्र सिंह
महाप्रबन्धक
स्वत्वाधिकारी, यू0पी0 कोऑपरेटिव यूनियन लि0, प्रकाशक, मुद्रक सुनील कुमार दिवाकर द्वारा सहकारी प्रेस, 14, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग लखनऊ, उ0प्र0 से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक-सुनील कुमार दिवाकर
फोन : 0522-4004577 (का.)
मोबाइल : 9415094114
ईमेल : sahkarita@gmail.com
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा।

नैनो यूरिया एवं नैनो डी0ए0पी0 का अधिक से अधिक करें प्रचार-प्रसार : श्रीकान्त गोस्वामी

❑ पॉस मशीन से उर्वरक वितरण के साथ-साथ कृषको को समिति पर बैठने की व्यवस्था के साथ सुचारू रूप से टोकन की व्यवस्था भी करने के निर्देश

बी-पैक्स महिमापुर, विकास खण्ड जमालपुर जनपद जौनपुर का भ्रमण श्रीकांत गोस्वामी अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ/प्रबंध निदेशक पी0सी0यू0/धान खरीद नोडल अधिकारी वाराणसी मंडल वाराणसी द्वारा किया गया। भ्रमण के समय उप आयुक्त एवं उप निबंधक सहकारिता वाराणसी मंडल के साथ साथ जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक महोदय की उपस्थिति मे बी-पैक्स महिमापुर की 10.00 लाख की ऋण सीमा स्वीकृत कराकर 10 मै0टन डी0ए0पी0 उपलब्ध कराते हुए कृषको को वितरित किया गया। नोडल अधिकारी द्वारा समिति सचिव एवं उपस्थित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि कृषको को उनकी जोत के अनुसार ही उर्वरक वितरण किया जाय। पॉस मशीन से उर्वरक वितरण के साथ साथ कृषको को समिति पर बैठने की व्यवस्था के साथ सुचारू रूप से टोकन की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए गये, जिससे कृषको को कोई असुविधा न हो। नैनो यूरिया एवं नैनो डी0ए0पी0 का प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक बिक्री करने के निर्देश दिए गये।

आर0 एन0 आई0 नं0 : 25008/72
डाक पंजी0 सं0 - GPO- LW/NP-178/2024-26
सहकारिता
उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन का दर्पण
वर्ष : 53 अंक : 05 (हिन्दी साप्ताहिक) लखनऊ-बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर, 2024 से 06 नवम्बर, 2024 पृष्ठ-4 वार्षिक 150.00 रूपया मात्र एक प्रति 3.00 रूपया

ग्राम पंचायतें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें हम अन्य लोगों के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकें : मुख्यमंत्री

❑ मिशन रोजगार के अन्तर्गत नवचयनित 1,526 ग्राम पंचायत अधिकारियों, 360 ग्राम विकास अधिकारियों (समाज कल्याण) एवं 64 पर्यवेक्षकों (समाज कल्याण) को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विगत साढ़े 07 वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के लिए तैयार की गई रूपरेखा के क्रम में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग्य व सक्षम युवाओं के चयन के अभाव में सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारना सम्भव नहीं होता है, क्योंकि अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से कार्य करने वाला तंत्र ही पैरालाइज हो जाता है। यह स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए वर्ष 2017 में ही प्रदेश सरकार ने तय किया था कि राज्य के सभी भर्ती बोर्ड आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न करें, ताकि युवाओं की योग्यता और क्षमता का उपयोग प्रदेश के विकास व राज्य के 25 करोड़ लोगों के भाग्य को बदलने के लिए किया जा सके। प्रदेश की जनता के सामर्थ्य से राज्य को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आज प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश को प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था छठवें तथा सातवें नम्बर पर थी। आज राज्य की अर्थव्यवस्था दो पर है।

मुख्यमंत्री यहां लोक भवन में मिशन रोजगार के अन्तर्गत नवचयनित 1,526 ग्राम पंचायत अधिकारियों, 360 ग्राम विकास अधिकारियों (समाज कल्याण) एवं 64 पर्यवेक्षकों (समाज कल्याण) के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए आगामी दीपावली पर्व का उपहार है। नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम लखनऊ के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मिशन रोजगार के विजन को आगे बढ़ाने तथा युवाओं को उनकी आकांक्षाओं एवं आशाओं के अनुरूप तथा उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार रोजगार प्रदान करने का अभियान है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विगत साढ़े 07 वर्षों में अब तक लगभग 07 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। प्रदेश में सुरक्षा के बेहतर वातावरण के कारण निजी क्षेत्र में भी लाखों युवाओं के लिए रोजगार की (शेष पृष्ठ 2 पर.....)

७१वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह
71st All India Cooperative Week
(१४ से २० नवंबर २०२४)/14th - 20st NOVEMBER 2024

७१वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह का मुख्य विषय
Main Theme of 71st All India Cooperative Week
"विकसित भारत के निर्माण में सहकारिताओं की भूमिका"
"Role of Cooperatives in Building Viksit Bharat"

विभिन्न दिनों के विषय
Nomenclature for Days

14-11-2024	सहकारिता मंत्रालय की नई पहलों के माध्यम से सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना Strengthening cooperative movement through new initiatives of Ministry of Cooperation
15-11-2024	सहकारी संगठनों में नवाचार, तकनीक और कुशल शासन Innovation, Technology and Good Governance in Cooperatives
16-11-2024	उद्यमिता, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने में सहकारिताओं की भूमिका The Role of Cooperatives in Fostering Entrepreneurship, Employment, and Skill Development
17-11-2024	सहकारी उद्यम में परिवर्तन Transforming Cooperative Enterprises
18-11-2024	सहकारी संगठनों के बीच सहयोग को मजबूत करना Strengthening Cooperation Among Cooperatives
19-11-2024	महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए सहकारी संगठन Cooperatives for Women, Youth, and Weaker Sections
20-11-2024	SDGs के ध्येय को हासिल करने में सहकारी संगठनों की भूमिका और बेहतर दुनिया के लिए आगे का मार्ग Role of Cooperatives in Achieving SDGs and way forward for Better World

आयुक्त एवं निबन्धक द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ के मुख्यालय भवन निर्माण हेतु मिली स्वीकृति

लखनऊ। उ0प्र0 सहकारिता विभाग के अन्तर्गत अनेक राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश संस्थाएँ अपने निजी कार्यालय भवनों में स्थापित हैं। उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ भी एक राज्य स्तरीय सहकारी शीर्ष संस्था है, जो वर्ष 2010 से राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है किन्तु इस संस्था का कोई निजी कार्यालय भवन नहीं था तथा संस्था का कार्यालय किराये के भवन में स्थापित है।

उक्त समस्या के निदान हेतु संस्था द्वारा वर्ष 2020-21 में आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना में एक संस्थागत भूखण्ड अपनी निजी आय से क्रय किया गया था जिसपर भूतल + 07 तलों के कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु संस्था द्वारा विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम संख्या 166 एवं नियम संख्या 176 में विहित प्राविधानों के तहत उक्त भवन निर्माण संघ की अपनी वित्तियोजित निधि से किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। स्वीकृति में कहा गया भवन निर्माण, संघ की अपनी वित्तियोजित निधि से होगा और सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा तथा OCeCC के उपरान्त भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तलों को किराये के लिए विभाग की सहकारी संस्थाओं, भारत सरकार, भारत सरकार की PSU, प्रदेश शासन, प्रदेश शासन के PSU को जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्धारित तत्समय के किराये के दर पर ही प्रस्तावित किये जायेंगे। प्रतिबन्ध यह भी रहेगा कि उपरोक्त में से उसी को प्रथमतः प्रस्तावित किया जायेगा जो प्राथमिकता में प्रथमतः सहकारिता के उद्देश्यों को बढ़ावा दे एवं कम से कम 3 महीने का किराया संघ को अग्रिम भुगतान करे।

बी.एन.सिंह आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता ने बताया कि संस्था के कार्यालय भवन का निर्माण पूर्ण हो जाने पर संस्था के कार्मिकों हेतु स्वस्थ कार्यदशायें एवं स्वस्थ वातावरण स्थापित होगा जिससे कार्मिकों की कार्यक्षमता/दक्षता में वृद्धि होगी, जो संस्था के व्यवसायिक प्रगति में सहायक होगी एवं सहकारिता के उद्देश्यों को प्रदेश में और प्रभावी तरीके आगे बढ़ाने में संस्था की भूमिका प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

धान क्रय केंद्रों की नियमितता, किसानों की सुविधाएं, और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के आदेश

धान खरीद प्रक्रिया, उज्जवला योजना और राशन कार्ड सत्यापन पर दिए निर्देश

लखनऊ। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक राज्यमंत्री सतीश शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त सौरभ बाबू, अपर आयुक्त कामता प्रसाद सिंह, वित्त नियंत्रक कमलेन्द्र कुमार, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान और मोटे अनाज की खरीद, उज्जवला योजना के तहत मुत गैस सिलेंडर वितरण और राशन कार्डों की ई-केवाईसी प्रक्रिया प्रमुख रूप से शामिल रहे।

आयुक्त ने जानकारी दी कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार ने धान के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, जिसमें कॉमन धान का मूल्य रूपये 2300 प्रति कुंतल और ग्रेड-ए धान का मूल्य रूपये 2320 प्रति कुंतल तय किया गया है। इस वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है और अब तक 17 जनपदों में 847 क्रय केंद्रों के माध्यम से 3790 किसानों से 21125 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों को रूपये 36 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। इस वर्ष प्रदेश में कुल 4000 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं।

मोटे अनाजों की खरीद के संबंध में, बाजरा, मक्का और ज्वार की खरीद जारी है। अब तक 781 किसानों से 3382 मीट्रिक टन बाजरा और 46 किसानों से 280 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद की जा चुकी है। बाजरा का समर्थन मूल्य रूपये 2625 प्रति कुंतल, ज्वार का रूपये 3371 प्रति कुंतल और मक्का का रूपये 2225 प्रति कुंतल तय किया गया है। मंत्री ने मोटे अनाज की खरीद योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने धान क्रय केंद्रों की नियमितता पर जोर देते हुए कहा कि ये (शेष पृष्ठ 2 पर.....)

संपादकीय

हमारा भारत देश एक अनोखा, महान कृषि एवं ग्रामीण प्रधान देश है। यहां की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यहां की अधिकांश जनता का मुख्य धन्धा कृषि है। यहां पर नानाप्रकार के खाद्यान्न एवं फलों का उत्पादन होता है। जरूरत है उन्हें आधुनिक (वैज्ञानिक) तरीके से उत्पादन करने की जिससे आम कृषक जन को कृषि उत्पादन विकास के साथ आर्थिक दृष्टि से भी भरपूर लाभ मिले। आम कृषक जन का आर्थिक विकास के साथ साथ तन-मन एवं शारीरिक रूप से भी हष्ट-पुष्ट रहने के लिए हमें अपने आहार में शामिल करने के लिए चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यथासंभव वे ही चुनें जो स्वास्थ्यवर्धक हो जिनसे शरीर स्वस्थ्य रहे। कोशिश यही होनी चाहिए कि शरीर की आवश्यकतानुसार आहार भी लिया जाए।

मानव स्वभाव सामान्यतः आलसी होता है। हर मनुष्य बच्चे, बूढ़े नौ जवान की आहार की आवश्यकता भी अलग-अलग होती है। आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा वाले व्यक्तियों का यह मानना है कि सही आहार ही हष्ट-पुष्ट रहने का मूल मंत्र एवं सभी रोगों का उत्तम इलाज भी। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिए आहार कैसा होना चाहिए। एक न्यूनतम प्रेषित के आहार में शामिल करने के लिए खाद्य पदार्थो की सूची, अतिरिक्त पोषित तथा सामान्य पोषित के आहार में शामिल होने वाली सूची से अलग होगी।

कुछ विद्धानों का विचार है कि बेसिक स्तर से ही बच्चों के पाठयक्रमों में पोषण पर एक सामान्य पाठयक्रम होना चाहिए, जिससे बच्चे भी पढ़ें और महत्व को समझे, लेकिन क्या बच्चे ही अपने बैग के बोझ से दबे जा रहे हैं। उन्हें और क्यों दबाएं उनके माता-पिता किस लिए हैं। ये जिम्मेदारी तो उनकी है जो बच्चों को खिलाएंगें वहीं खाएंगे। वैसे इसे बच्चों के माता-पिता को अच्छी तरह से समझना ही चाहिए।

एक सामान्य साधारण सर्वे से मालुम हुआ कि विदेशों में लगभग 40 प्रतिशत डाक्टर एवं 50 प्रतिशत आम जनता को मालुम नहीं कि खाद्य पौष्टिकता की समुचित जानकारी नहीं हैं। तो भारत जैसे विशाल देश एवं ग्रामीण प्रधान होने के कारण कुछ कहना ही मुश्किल है कि कितनी जनता को खाद्य पौष्टिकता के विषय में जानकारी है। यहां तक कि डाक्टर भी उचित सलाह देने से जैसे कतराते हैं। कौन-कौन सी वस्तुएं खाद्य पौष्टिकता की श्रेणी में आती हैं और उन्हें कब खाना देना चाहिए कब नहीं। बहुत ही कम डाक्टर भी इसकी सलाह देते हैं। पूछने पर बताते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में सब चीजें खाइए किसी भी वस्तु से परहेज नहीं है। जबकि स्वस्थ्य रहने के लिए उचित सलाह लेना एवं देना डाक्टर और मरीज (सामान्य जनता) की जिम्मेदारी है। ❑

किसानों को औद्यानिक फसलों से अधिक लाभ मिल सकें इसके लिए विदेशों से उन्नत बीजों से तैयार पौध दिये जायें

❑ किसानों, जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए

- मंत्री दिनेश प्रताप सिंह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर तक ले जाने के लिए विभागों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये गये है। उक्त के क्रम में प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने उद्यान विभाग की योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये है। अपर मुख्य सचिव स्तर द्वारा योजनाओं की समीक्षा 15 दिनों में की जायेगी। योजनाओं की माहवार समीक्षा स्वंय मंत्री के द्वारा की जाएगी।

उद्यान मंत्री ने मंत्री आवास में विभाग की मौजूदा योजनाओं और उनकी प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं को सरल करते हुए प्रदेश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और सफलता की कहानियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

वैल्यू एडेड औद्यानिक फसलों पर विशेष जोर देते हुए उद्यान मंत्री ने कहा कि औषधीय और फूलों जैसी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पौधे उपलब्ध कराने हेतु तुर्की से उन्नत बीज मंगवाने और उत्तर प्रदेश के जलवायु के अनुसार औद्यानिक फसलों का चयन कर किसानों को पौध तैयार करके दी जाए।

श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में एकी.त पैक हाउस के निर्माण की योजना के अन्तर्गत फतेहपुर, आगरा और बहराइच में पैक हाउस स्थापित किए जाएंगे, जो किसानों की उपज के भंडारण और पैकेजिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। इन पैक हाउसों से ,षि उत्पादों के बेहतर प्रबंधन और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि किसानों, जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके।

पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक के संचालन हेतु 87.55 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 87.55 (रूपये सत्तासी लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

शासनादेश में निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 03 प्रतिशत की वृद्धि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन में महगाई भत्ते की 03 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। अब कर्मचारियों का महगाई भत्ता बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार द्वारा आज शासनादेश जारी कर दिया गया है।

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओ, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियो, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारको को महंगाई भत्ते का 01 जुलाई 2024 से बढ़ी हुई दरों पर भुगतान किया जायेगा। स्वी.त दरों पर महगाई भत्ते को 01 जुलाई 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक देय अवशेष धनराशि अधिकारी एवं कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी। दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से देय धनराशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2024 के नियमित वेतन के साथ दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 को नकद किया जायेगा।

पृष्ठ 1 का शेष...धान क्रय केंद्रों की नियमितता....

केंद्र प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुलें और केंद्र प्रभारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए बैठने, पानी, छाया और धान सुखाने की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

अपर आयुक्त ने बैठक में अवगत कराया कि प्रदेश के 1.86 करोड़ उज्जवला लाभार्थियों को दीपावली के अवसर पर मुत सिलेंडर वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण में आधार सत्यापित 1.08 करोड़ लाभार्थियों को सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, जो 31 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। मंत्री ने शेष लाभार्थियों का आधार प्रमाणन शीघ्र पूर्ण करने और इस योजना का अधिकतम प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्यमंत्री ने राशन कार्ड सत्यापन और ई-केवाईसी कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में 9.40 करोड़ यूनिट्स की ई-केवाईसी कराई जा चुकी है, जो कुल यूनिट्स का 62.66 प्रतिशत है। उन्होंने शेष लाभार्थियों की ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन कर उन्हें योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपात्र और निष्क्रिय कार्डधारकों के राशन कार्डों का निरसन कर पात्र गृहस्थियों को राशन कार्ड वितरित किए जाएं।

प्रदेश में अब तक 2961 माडल उचित दर दुकानों का निर्माण किया जा चुका है। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विकास खंड में अधिकतम माडल दुकानों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को खाद्यान्न वितरण की सुविधाएं बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो सकें। मंत्री ने उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण में विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य प्राप्त करने और घटतौली की शिकायतों के प्रति सख्त रूख अपनाते हुए निर्देश दिए कि अधिकारियों द्वारा न्यूनतम 10 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही, पीडीएस वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाए और खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जाए। विभागीय गोदामों को किरायेदारी से मुक्त कराने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। पीडीएस के तहत वितरित फोर्टीफाइड चावल की गुणवत्ता नियमित रूप से चेक की जाए। सिंगल स्टेज परिवहन के अंतर्गत निर्धारित संख्या में छोटे और बड़े वाहन उपलब्ध कराए जाएं और उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

पृष्ठ 1 का शेष.....ग्राम पंचायतें ऐसी होनी चाहिए .....सम्भावनाओं को आगे बढ़ाया गया है। पहले प्रदेश में निवेशक निवेश करने से कतराते थे। अब यहां बड़े-बड़े निवेश किये जा रहे हैं। लाखों-करोड़ों रूपए के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। वर्तमान में लाखों-करोड़ों रूपए के निवेश प्रदेश सरकार द्वारा विचाराधीन हैं। इस प्रक्रिया को बहुत शीघ्र सम्पन्न किया जाएगा। यह निवेश केवल निवेश नहीं है, बल्कि इसमें रोजगार तथा विकास भी सम्मिलित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का युवा नौकरी व रोजगार के लिए देश व दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में भटकता था। युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज युवाओं को अपने ही प्रदेश, जनपद व क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है। युवा प्रदेश में रहकर देश की अर्थव्यवस्था को सु.ढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। युवा अपने परिवार की अच्छे ढंग से देखभाल व घर के कार्यों के साथ-साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। शासन तथा निजी क्षेत्र हेतु योग्य तथा स्किल्ड मैनपावर उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत ट्रेड तथा कोर्सेज संचालित किए गए हैं। इसके लिए बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास किया गया है। इसी का परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। यहां विकास का वातावरण तैयार हुआ है। निवेश के माध्यम से रोजगार की अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। वर्ष 2017 से पूर्व युवाओं के योग्य व सक्षम होने के बावजूद उन्हें भ्रष्टाचार तथा भेदभाव के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था।

मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए ग्राम पंचायत सर्वाधिक आधारभूत इकाई है। आप सभी को इस आधारभूत इकाई को और अधिक सुदृढ़ करने में अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए देशवासियों को लक्ष्य प्रदान किया है कि जब वर्ष 2047 में भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब भारत आत्मनिर्भर और विकसित होना चाहिए। जो नींव आज आप रखेंगे वही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। इसमें ग्राम पंचायतें अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगी। इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने अनेक कार्य पहले से सम्पन्न कर लिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। इन कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश स्तर पर सचिवालय, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के कार्यालय और विकास भवन अब प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं। इनमें आप्टिकल फाइबर या इण्टरनेट का कनेक्शन अथवा वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति भी की जा चुकी है। अब आपको वहां पर स्वयं को साबित करना होगा। गांव के लोगों की समस्या का समाधान गांव में ही होना चाहिए। आय, निवास तथा जाति प्रमाण पत्र आदि सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत को तैयार करना होगा। ग्राम पंचायत की कार्य योजना को ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से जुड़े हुए अन्य लोगों के साथ बैठकर तैयार करना होगा।

महिला सशक्तिकरण व स्वावलंबन के लिए सरकार संकल्पबद्ध

लखनऊ। पूर्व विधायक स्व उपेन्द्र तिवारी की पुण्यस्मृति के अवसर पर अपने शाहाबाद (जनपद हरदोई) आगमन के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने बड़ा मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उनके द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाईकिल वितरित की गयी। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों की सराहना की। जिला कार्यक्रम विभाग के स्टाल पर उन्होंने अन्नप्राशन व गोद भराई संस्कार कराया।

अपने सम्बोधन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक आवासहीन पात्र व्यक्ति को आवास उपलब्ध करा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाये गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टूलकिट व प्रमाणपत्र प्रदान किये। उनके द्वारा बटन दबाकर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया।

राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा श्रीमती रजनी तिवारी ने पूर्व विधायक स्व उपेन्द्र तिवारी के योगदान को याद किया तथा कहा कि सरकार की योजनाओं में का लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिया जा रहा है।

इस अवसर पर राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल, प्रभारी मंत्री असीम अरूण, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती, सांसद हरदोई जयप्रकाश, विधायक सवायजपुर माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू, अजीत सिंह बब्बन व अन्य जनप्रतिनिधिगण व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

पंचायती राज संस्थाओं हेतु 800 करोड रुपए की धनराशि स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अक्टूबर, 2024 के लिए 800 करोड़ रूपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। स्वीकृत धनराशि में जिला परिषद एवं जिला स्तरीय पंचायतों हेतु 120 करोड़ रूपए, ब्लाक पंचायतों अथवा मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों हेतु 120 करोड़ रूपए तथा ग्राम पंचायतों हेतु 560 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जारी आदेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का जिला परिषदों अथवा जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों अथवा मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार किया जाएगा। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे।

नगर निकायों हेतु 1200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर नगर निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अक्टूबर, 2024 के लिए 1200 करोड़ रूपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। स्वीकृत धनराशि में नगर निगमों हेतु 540 करोड़ रूपए, नगर पालिकाओं, नगर पालिका परिषदों हेतु 420 करोड़ रूपए तथा नगर पंचायतों हेतु 240 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

जैविक कृषि आधारित उद्यमिता पर आयोजित हुई कार्यशाला

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्यालय के सभागार में "जैविक कृषि आधारित कृषि उद्यमिता एवं ग्रामोद्योग से स्वरोजगार" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड डा. उज्ज्वल कुमार ने कार्यशाला में उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्राथमिकता के आधार पर नाबार्ड, सीमैप, एन.बी.आर.आई. और उद्यान विभाग आदि से समन्वय स्थापित कर ग्रामोद्योग के माध्यम से नवाचार एवं रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

इस कार्यशाला में पद्मश्री डा. भारत भूषण त्यागी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक कृषि आधारित उद्यमिता की स्थापना हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में पी. एस. ओझा, पूर्व राज्य सलाहकार, जैविक ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने सहकारिता एवं एफ.पी.ओ. के माध्यम से ग्रामोद्योगी रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही, सीमैप, नाबार्ड, उद्यान विभाग और एन.बी. आर.आई. से आए वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने भी बहुमूल्य जानकारी साझा की।

इस कार्यशाला में खादी बोर्ड के मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्रों के प्राचार्य, परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी और खादी बोर्ड मुख्यालय के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सीड पार्क जैसे प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता

कृषि सेक्टर में सीड इकोसिस्टम को बेहतर करना होगा-सी.एम.

किसानों को दलहन, तिलहन, मिलेट अन्न की बुआई के लिए प्रोत्साहित करते हुए, फसल विविधीकरण एवं बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बेहतर करने की आवश्यकता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीतियों की समीक्षा की। बैठक में मंत्रीगण, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों तथा विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने सभी 10 सेक्टर्स में जारी कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर कंसल्टिंग एजेंसी डेलायट इण्डिया ने प्रदेश के आर्थिक परिवेश की वर्तमान स्थिति और सम्भावित भावी परिणामों, उद्योग जगत की अपेक्षाओं आदि के सम्बन्ध में सेक्टरवार विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 07 वर्षों के नियोजित प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश की कुल जी0डी0पी0 16.45 लाख करोड़ रूपये थी, जो वर्ष 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गई है। इस वर्ष हमारा जी0एस0डी0पी0 लक्ष्य 32 लाख करोड़ रूपये है। सभी के सहयोग से यह लक्ष्य भी पूरा होगा। इन 07 वर्षों में प्रदेश की जी0डी0पी0 और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हुई है। प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है।

प्रदेश में सेक्टरवार विकास के प्रयासों के आशातीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अलग-अलग सेक्टरों के लिए सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) के लक्ष्य के सापेक्ष अधिक वृद्धि देखी गई है। कृषि और सहायक सेक्टर के लिए अनुमानित जी0वी0ए0 5.85 लाख करोड़ रूपये के सापेक्ष 5.98 लाख करोड़ रूपये, विनिर्माण के 2.48 लाख करोड़ रूपये के सापेक्ष 2.79 लाख करोड़ रूपये, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन के अनुमानित जी0वी0ए0 के सापेक्ष 129 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। स्पष्ट है कि व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण से सम्बन्धित संचार सेवाओं की वृद्धि दर में तेजी आई है। यही स्थिति अन्य सेक्टरों में भी है। ओवरआल वर्ष 2023-24 में राज्य के लिए अनुमानित जी0एस0वी0ए0 23 लाख करोड़ रूपये के सापेक्ष सकल मूल्य वर्धन 23.24 लाख करोड़ रूपये रहा है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी (ओ0टी0डी0ई0) के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्य बड़ा है। पिछले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी विभागों की सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हमारी नीति और नियोजन सही है। बड़े लक्ष्य के लिए अपनी गति तेज करने की आवश्यकता है। इसकी नियमित मानीटरिंग होनी चाहिए। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। नोडल अधिकारी साप्ताहिक, प्रमुख सचिव स्तर पर पाक्षिक और विभागीय मंत्री के स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक की जाए।

आंकड़ों का संग्रहण शुद्धता के साथ होना आवश्यक है। इसके लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम0ओ0एस0पी0आई0) से संवाद व समन्वय बनाएं तथा उनके अनुभवों का लाभ लें। सही आकलन के लिए विभागवार सांख्यकीय अधिकारियों के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन करें। डेटा जितना शुद्ध होगा, लक्ष्य के लिए हम उतना ही बेहतर प्रयास कर सकेंगे। वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (सी0ए0जी0आर0) लगभग 16 प्रतिशत दर्ज किया गया है। यह स्थिति उत्साहजनक है। वर्तमान वर्ष के लिए 25 प्रतिशत का लक्ष्य है। सभी विभागों को अपने प्रयास तेज करने होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। सभी को मिलकर सही नीति और नियोजित क्रियान्वयन के लिए प्रयास करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक सेक्टर में अवसर हैं, हमें नवाचारों को बढ़ावा देना होगा। कृषि सेक्टर में सीड इकोसिस्टम को बेहतर करना होगा, इसके लिए सीड पार्क जैसे प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। किसानों को दलहन, तिलहन, मिलेट अन्न की बुआई के लिए प्रोत्साहित करते हुए, फसल विविधीकरण एवं बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बेहतर करने की आवश्यकता है।

कृषि मंत्री ने गोरखपुर में मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में की भागीदारी

लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बुधवार को जनपद गोरखपुर में गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ मण्डल की 'मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी-2024' में सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर उन्होंने किसानों को सम्बोधित किया तथा 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना' के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने लिए योजना के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किये। उन्होंने 'जिला औद्यानिक मिशन योजना' के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किये एवं 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना' के लाभार्थियों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रूपये 04 लाख की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया।

इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ल, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका गर्ग, सचिव कृषि अनुराग यादव, सचिव ग्राम्य विकास सुखलाल भारती, आयुक्त गोरखपुर अनिल ढींगरा, आयुक्त आजमगढ़ मनीष चौहान, आयुक्त बस्ती अखिलेश सिंह, निदेशक कृषि उपस्थित रहे।